

पंकज मेहरा और अन्य

बनाम

महाराष्ट्र राज्य और अन्य

फरवरी 15, 2000

[के.टी. थॉमस और ए.पी. मिश्रा, जे.जे.]

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881- धारा 138- एक कंपनी द्वारा जारी चेक का अनादर- धारा 138 के तहत आपराधिक अभियोजन- मुख्यतः निर्णयः कंपनी धारा 138 के तहत दंडात्मक दायित्व से इस आधार पर बच नहीं सकती कि प्रासंगिक समय के दौरान कंपनी को बंद करने की याचिका लंबित थी- कंपनी अधिनियम, 1956- धारा 441 (2), 536(2)

कंपनी अधिनियम, 1956 -धारा 441(2), 536(2)- किसी कंपनी को बंद करना- शुरुआत- समापन के बाद हस्तांतरण आदि के की साक्ष्य - कंपनी द्वारा किसी भी संपत्ति का निपटान याचिका की प्रस्तुति पर तुरंत 'शून्य' नहीं होगा - कंपनी इस आधार पर परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत अपने दंडात्मक दायित्व को भी टाल नहीं सकती है कि समापन याचिका प्रासंगिक समय के दौरान लंबित थी- परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881- धारा 138

भुगतान के लिए चेक प्रस्तुत किए जाने पर एक कंपनी द्वारा जारी किए गए चेक का भुगतान करने वाले बैंक द्वारा 26.12.1996 पर अनादर किया गया था। चेक प्राप्तकर्ता द्वारा कंपनी को राशि का भुगतान करने के लिए एक नोटिस जारी किया गया और राशि का भुगतान करने में विफल रहने के कारण, कंपनी और उसके निदेशकों के खिलाफ परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध के लिए 29.1.1997 पर एक आपराधिक शिकायत दर्ज की गई। कंपनी ने आपराधिक कार्यवाही को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की जिसमें कहा गया था कि कंपनी को बंद करने के लिए एक याचिका 27.5.1996 पर दायर की गई थी, इसलिए, कंपनी की संपत्ति का कोई भी निपटान अमान्य होगा यदि वह कंपनी को बंद करने की याचिका प्रारंभ होने के बाद किया गया था। रिट याचिका को खारिज करते हुए, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने कहा कि केवल मात्र इसलिए कि समापन के लिए याचिका प्रस्तुत की गई है इस अवधि के दौरान सभी लेन-देन या कार्य शुरू से ही अमान्य नहीं हो सकते हैं कि कंपनी अधिनियम की धारा 441(2) सपठित धारा 536(2) में प्रावधान के तहत कानूनी कल्पना के आधार पर जो अन्यथा वैध था उसे शून्य में परिवर्तित करना है, और इस प्रकार कंपनी समापन या अस्थायी परिसमापक की नियुक्ति के आदेश के पारित होने पर रद्द किया जा सकने वाला लेन-देन या कार्य शून्य होता है और धारा 441(2) की कानूनी कल्पना से यह फिर पूर्व निर्धारित तिथि से संबंधित मन्य होता है। इसलिए

यह अभिनिर्धारित किया गया कि कंपनी केवल इस आधार पर अपने दायित्व को टाल नहीं सकती कि कंपनी को चेक की राशि का भुगतान करने का नोटिस दिए जाने से पहले समापन याचिका प्रस्तुत की गई थी।

ये अपीलें उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर की गई थीं। विचार के लिए उठाया गया सवाल यह था कि क्या कोई कंपनी परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत दंडात्मक दायित्व से इस आधार पर बच सकती है कि एक याचिका प्रस्तुत की गई थी और जो प्रासंगिक समय के दौरान लंबित थी ?

अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि एक चेक जारी करने से ही संपत्ति का निपटारा होता है और कंपनी अधिनियम की धारा 536(2) के तहत कंपनी की संपत्ति का कोई भी निपटान शून्य होगा यदि यह परिसमापन की कार्यवाही शुरू होने के बाद किया गया था तथा कंपनी अधिनियम की धारा 441(2) के प्रावधान के अनुसार, अदालत द्वारा किसी कंपनी को बंद करने की कार्यवाही याचिका प्रस्तुत करने के समय से मानी जाएगी; चूंकि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध का गठन करने की शर्तों में से एक यह है कि कानूनी रूप से लागू करने योग्य 'ऋण या अन्य दायित्व' के निर्वहन के लिए चेक जारी किया जाना चाहिए था, इसलिए इस तरह की स्थिति में ऐसा कोई चेक संभव नहीं हो सकता है

क्योंकि लेनदार परिसमापन कार्यवाहियों की शुरुआत के साथ ऋण को कानूनी रूप से लागू करने से अक्षम हो जाएगा ।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने-

निर्णय: 1.1 . कंपनी अधिनियम की धारा 536(2) में "शून्य" शब्द यह स्वचालित रूप से इंगित नहीं करता है कि कोई भी निपटान शुरू से ही शून्य होना चाहिए। "शून्य" शब्द का कानूनी निहितार्थ आवश्यक रूप से सभी आकस्मिकताओं में शून्यता का चरण नहीं होना चाहिए। शून्य शब्द का उपयोग आकस्मिक रूप से नहीं किया जाता है क्योंकि अदालत के पास अन्यथा आदेश देने की शक्ति है। "जब तक अदालत अन्यथा न आदेश करें" शब्द "शून्य" शब्द की कठोरता को कम करते हैं और उस शब्द से जुड़े वैकल्पिक अर्थ को चुनने में सक्षम हैं।

1.2. यह निर्धारित करना ठीक नहीं है कि कंपनी बंद करने की याचिका प्रस्तुति करने और बंद करने के लिए आदेश के पारित होने के बीच के अंतराल के दौरान कंपनी द्वारा किए संपत्ति के सभी निपटान अमान्य और शून्य होंगे। यदि इस तरह का दृष्टिकोण अपनाया जाता है तो कंपनी का व्यवसाय ठप हो जाएगा, क्योंकि, कंपनी को बहुत सारे दिन-प्रतिदिन के लेनदेन से निपटना पड़ सकता है, कर्मचारियों और अन्य को वेतन का भुगतान करना पड़ सकता है और तत्काल आकस्मिकताओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी व्याख्या को टाला जाना चाहिए जो ऐसी

विनाशकारी स्थिति का कारण बन सकती है। इसके अलावा, यदि ऐसा कोई दृष्टिकोण अपनाया जाता है, तो एक धोखाधड़ी वाली कंपनी ऐसे ईमानदार ग्राहकों को हराने के लिए कंपनी को बंद करने के लिए प्रस्तुत की जाने वाली याचिका का प्रबंधन करके चरणबद्ध तरीके से कंपनी के साथ व्यापार करने वाले किसी भी ईमानदार व्यक्ति को धोखा दे सकती है।

1.3. यदि भुगतान शुरू से ही अमान्य नहीं है तो कंपनी यह विरोध नहीं कर सकती कि चेक के अनादर के संबंध में जब प्राप्तकर्ता द्वारा नोटिस जारी किया गया था तो चेक राशि का भुगतान करने से कानूनी रूप से मना किया गया था।

1.4. चेक बैंकर को राशि का भुगतान उसके धारक को करने का आदेश हो सकता है और संपत्ति का कोई निपटान तब तक नहीं होगा जब तक इसके अनुसार बैंकर द्वारा भुगतान नहीं कर दिया जाता है। अधिक से अधिक, चेक जारी करने को संपत्ति के निपटान की दिशा में एक कदम के रूप में माना जा सकता है, लेकिन यह संपत्ति के निपटान के लिए अपर्याप्त है।

1.5. कंपनी अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो किसी कंपनी से देय ऋण के प्रवर्तन को प्रतिबंधित करता हो। जब कोई कंपनी परिसमापन में जाती है, कंपनी से देय ऋण का प्रवर्तन केवल समापन में अंकित शर्तों के अधीन होता है। लेकिन इससे यह मानने के लिए कोई

आधार नहीं है कि ऋण कानूनी रूप से अप्रवर्तनीय है। शायद कंपनी के पास पर्याप्त संपत्ति नहीं होने से ऋण की वसूली कठिन होगा। इससे यह नहीं माना जा सकता कि ऋण कानूनी रूप से अप्रवर्तनीय है। ऋण की प्रवर्तनीयता का परीक्षण प्राप्ति या पुनर्प्राप्ति के लिए प्रदान की गई पद्धति या प्रक्रिया की कसौटी पर नहीं किया जाना चाहिए।

1.6. परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 ने एक विधिक अपराध बनाया है जो उसमें अंकित किए गए विभिन्न कारकों का संगम है, जो चेक के आहरण के साथ शुरू होता है और चेक के लेखीवाल द्वारा निर्धारित समय के भीतर उसके द्वारा चेक राशि का भुगतान करने में विफलता के साथ समाप्त होना दंडात्मक दायित्व में बदल जाता है। विधायिका ने अन्य अभिव्यक्तियों के बजाय सोच-समझकर "विफल" शब्द का उपयोग किया है क्योंकि विफलता विभिन्न कारणों से हो सकती है जिसमें भुगतान करने की अक्षमता भी शामिल है। लेकिन अपराध तब पूरा होगा जब लेखीवाल निर्धारित समय के भीतर भुगतान करने में विफल रहता है, इस तरह की विफलता का कारण जो भी हो।

1.7. चेक के लेखीवाल के पास चेक राशि का भुगतान करने में विफलता के लिए अलग-अलग स्पष्टीकरण हो सकते हैं। लेकिन इस तरह का कोई भी स्पष्टीकरण उसे अपराध के जाल से बाहर निकालने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। अपराध की कठोरता को कम करने के लिए शायद किसी प्रकार

के स्पष्टीकरण पर्याप्त होंगे जो अधिरोपित किए जाने वाले दंड की मात्रा को कम के लिए उपयोगी हो।

चित्र जिला सहकारी मार्केटिंग सोसायटी लिमिटेड v. मेसर्स वेगेटोल्स लिमिटेड और अन्य, [1987] Suppl. SCC 167, पर सहारा लिया।

तुलसीदास जसराज पारेख बनाम इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ वेस्टर्न इंडिया, AIR (1931) Bom 2; नवजीवन मिल्स लिमिटेड में गुजरात उच्च न्यायालय, In re, (1986) 59 Company Cases 201, मामलों की पुष्टि की गई।

रे ग्रेज इन कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (1980) 1 ALL ER 814, से भेद किया गया।

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय: आपराधिक अपील सं 11/1999 इत्यादि इत्यादि ।

बंबई उच्च न्यायालय के Cri.W.P सं. 324/1998 में पारित निर्णय और आदेश दिनांकित 25/26.6.98 से।

पी. चिदंबरम, टी. आर. अंधारुजिना, अशोक एच. देसाई, एम. ऐसे. गणेश, एम. एन. राव, टी. एल. वी. अय्यर, दुष्यंत ए. डेव, यू. एन. बचावत, डी. ए. डाइव, एफ. ऐसे. नरीमन, कपिल सिब्बल, हरीश एन. साल्वे, जे. ऐसे. गोस्वामी, सुश्री बीना गुप्ता, प्रशांत नाइक, सुश्री रेखा रे,

श्रीमती उर्मिला सिरूर, निखिल नायर, सी. एल. सरीन, राजीव दत्ता, सुश्री एनाक्षी कुलश्रेष्ठ, उदय कुमार, कपिल शर्मा, साठे, नितिन तमस्वेकर, आलोक सेन गुप्ता, रंजन नरियन, सुश्री दीपा दास, सुश्री लावण्या, सुश्री विवेक जुत्शी, ऐसे. सुकुमारन, यू. यू. ललित, सुश्री एच. वाही, सुश्री अनु साहनी, अशोक गुप्ता, आर. शशिप्रभु, ए. पी. विनोद, मनोज प्रसाद, मोहित माथुर, सुश्री आस्था त्यागी, ऐसे. प्रसाद, वी. ए. राणा, राजेश नायर, ई. आर. कुमार, आर. नेदुमारन, पवन कुमार, कैलाश वासदेव, आर. रहीम, वी. बी. जोशी, सुश्री श्वेता शर्मा, जी. प्रभाकर, सुश्री टी. अनामिका, कृष्णमूर्ति स्वामी, ऐसे. ऐसे. राणा, श्रीमती बिंद्रा राणा, विक्रान्त राणा, के. मारुति राव, श्रीमती के. भारती, डी. महेश बाबू, पी. ऐसे. नरसिम्हा, सुश्री बी. श्रीधर, नंदिनी गोरे, अरुणाभा चौधरी, सुश्री माणिक करंजावाला, रमेश सिंह, नरिस बीरानी, पी. नीरोप, बी. पी. पैडी, पवन कुमार, सी. ऐसे. सरीन, पंकाज मेहरा, मनीष गर्ग, ऐसे. प्रसाद, डी. एम. नरगोलकर, चंद्र भूषण ए. एन. खान विल्कर, सुश्री राखी रॉय, एम. के. सिंह, सातू भल्ला और मीनाक्षी कुलश्रेष्ठ उपस्थित पक्षकारों के लिए ।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था-

थॉमस, न्यायाधिपति : क्या कोई कंपनी परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत दंडात्मक दायित्व से इस आधार पर बच

सकती है कि एक याचिका प्रस्तुत की गई थी और जो प्रासंगिक समय के दौरान लंबित थी ?

बंबई उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि कंपनी केवल इस आधार पर अपने दायित्व को टाल नहीं सकती कि चेक की राशि का भुगतान करने के लिए कंपनी को दिए नोटिस से पूर्व ऐसी याचिका प्रस्तुत की जा चुकी थी। ऐसा मानते हुए, खंड पीठ ने विभिन्न कंपनियों द्वारा दायर रिट याचिकाओं के एक समूह को खारिज कर दिया, जिसमें उनके खिलाफ विभिन्न आपराधिक अदालतों में शुरू की गई परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत आपराधिक कार्यवाही को चुनौती दी गई थी। अब हमें विशेष अनुमति द्वारा दायर अपीलों के इस समूह में उसी प्रश्न से निपटना है।

हालाँकि अब हमारे सामने अलग-अलग मामलों में अलग-अलग तथ्य हैं, लेकिन हमें इस तरह के मतभेदों से खुद को परेशान नहीं करना है । सभी में सामान्य विशेषताएँ हैं, जो केवल उपरोक्त प्रश्न से निपटने के लिए प्रासंगिक हैं, जिन्हें किसी एक अपील से निकाला जा सकता है। उक्त नमूना अपील में शामिल कंपनी को "कंपनी" के रूप में संदर्भित किया जाएगा। कंपनी द्वारा चेक जो जारी की गई उसकी तारीख 30.10.1996 थी (एक तर्क है कि चेक वास्तव में उस तारीख से बहुत पहले तैयार किया गया था) और चेक द्वारा कवर की गई राशि रूपए 5,72,432 थी। जब चेक

नकदीकरण के लिए प्रस्तुत किया गया था तो ऊपरवाल बैंक ने 26.12.1996 को इसका अनादरण किया। चेक के प्राप्तकर्ता ने राशि का भुगतान करने के लिए 21.12.1996 पर कंपनी को नोटिस जारी किया। चूंकि कंपनी राशि का भुगतान करने में विफल रही, इसलिए परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध के लिए कंपनी और उसके दो निदेशकों के खिलाफ मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज की गई।

अपराध का संज्ञान लेने वाले मजिस्ट्रेट ने सभी अभियुक्त को तामिलें जारी की। आरोपी ने आपराधिक कार्यवाही को इस आधार पर चुनौती दी कि कंपनी को बंद करने के लिए एक याचिका संबंधित अदालत के समक्ष 27.5.1996 पर दायर की गई है और उस अदालत द्वारा एक अस्थायी परिसमापक दो साल बाद यानी 21.4.1998 पर नियुक्त किया गया था।

जैसा कि ऊपर बताए गए तथ्य काफी हद तक विवादित नहीं थे, उच्च न्यायालय की पीठ ने इस सीमित प्रश्न पर बैच की अन्य रिट याचिकाओं के साथ रिट याचिका पर सुनवाई शुरू की कि क्या कंपनी इस आधार पर दंडात्मक दायित्व को टाल सकती है। कंपनी द्वारा अभियोजन का विरोध मुख्यतः इस आधार पर किया गया कि कंपनी अधिनियम की धारा 536(2) के तहत कंपनी की संपत्ति का कोई भी निपटान शून्य होगा यदि इसे समापन शुरू होने के बाद किया गया था। उक्त आधार

को मजबूत करने के लिए कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम की धारा 441(2) को आधार बनाया गया जो कहती है कि न्यायालय द्वारा किसी कंपनी का समापन उसकी याचिका की प्रस्तुति के समय से माना जाएगा। उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने सभी मामलों में सामान्य विशेषताओं पर ध्यान देकर निम्नलिखित कथन किया:

"इन सभी मामलों में, समापन के लिए एक याचिका दायर की गई थी जो चेक जारी होने से पहले (कुछ मामलों में) और किसी भी स्थिति में नोटिस प्राप्त होने के बाद 15 दिनों की अवधि समाप्त होने से पहले दायर की गई थी। इस प्रकार विचार के लिए प्रश्न यह है कि क्या केवल समापन याचिका प्रस्तुत कर देने से भुगतान करने पर रोक या कानूनी विकलांगता आ जाती है।"

विद्वान न्यायाधीश उपरोक्त स्वीकृत आधार पर प्रश्न पर विचार करने के लिए आगे बढ़े और इसलिए, इस तर्क की जांच की कि क्या कंपनी द्वारा किसी भी संपत्ति का निपटान समापन के लिए याचिका प्रस्तुत करने पर तुरंत "शून्य" हो जाएगा, या जब केवल समापन का आदेश पारित होगा तब शून्य होगा, या जब अस्थायी परिसमापक नियुक्त किया जाएगा। कंपनी अधिनियम की धारा 536(2) की व्याख्या एक व्यापक आयाम में करने की मांग की गई थी ताकि सभी लेन-देन केवल इसलिए अमान्य हो जाए

क्योंकि समापन के लिए एक याचिका प्रस्तुत की गई थी- चाहे वह एक अस्थायी परिसमापक नियुक्त करने या कंपनी को समाप्त करने के आदेश द्वारा सफल हुई हो या नहीं। उच्च न्यायालय की खंड पीठ उक्त तर्क को निम्नलिखित तर्क पर खारिज कर दिया:

"यदि इस तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है, तो जिन व्यक्तियों ने बंद करने की याचिका प्रस्तुत करने के बारे में कोई जानकारी बिना स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से खुले बाजार में शेयर खरीदे हैं, वे भी प्रभावित होंगे क्योंकि ऐसे सभी लेनदेन अमान्य होंगे। इसलिए, यदि इस व्यापक प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना था, तो एक बार समाप्त करने के लिए एक याचिका प्रस्तुत की जाती है, समाप्त करने के आदेश के बिना ही सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए कंपनी का बंद होना माना जाएगा।

कंपनी की सभी गतिविधियां रुक जाएगी। अगर ऐसा कानून होता तो बेईमान पक्ष अनुचित मांगों को मनवाने के लिए केवल समाप्त करने के लिए याचिकाएं प्रस्तुत करने की धमकी देकर सभी कंपनियों को ब्लैकमेल/दबाव बनाता। इसके विपरीत एक बेईमान कंपनी अपने स्वयं के पक्षों द्वारा फर्जी याचिकाएँ प्रस्तुत करवाके देनदारियों से बचती। जो एक के खारिज होने के बाद दूसरी दायर की जा सकती है। इस तरह से कंपनी अपनी देनदारियों का निर्वहन करने के अगर स्थायी रूप से नहीं तो निश्चित रूप से बच सकती है। यदि केवल कानून अनुसार समाप्त करने के लिए

याचिका दायर करना सभी लेनदेन को शून्य करना था, तो यह बेतुके या विनाशकारी परिणामों की ओर ले जाएगा। हमारी राय में यह कभी भी कानूनी स्थिति नहीं हो सकती है।

तब डिवीजन बेंच के समक्ष यह तर्क दिया गया कि कंपनी अधिनियम की धारा 536(2) में दिखाई देने वाला शब्द "समापन के दौरान" का अर्थ है "समापन कार्यवाही के दौरान"। इसका सहारा *कमानी मैटेलिक ऑक्साइड लिमिटेड बनाम कमानी ट्यूब्स लिमिटेड, (1984)* कंपनी केस पेज 19, में पारित निर्णय पर रखा गया था, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि "समापन में" शब्दों का अर्थ "समापन आदेश के पारित होने पर या बाद में" नहीं है। उच्च न्यायालय की खंड पीठ के विद्वान न्यायाधीश ने उक्त मामले में विशिष्ट संदर्भ की ओर इशारा किया जिसमें ऐसा दृष्टिकोण लिया गया था और फिर यह विचार व्यक्त किया कि केवल इसलिए कि समापन के लिए एक याचिका प्रस्तुत की गई है, इस अवधि के दौरान सभी लेनदेन या निपटान किए गए आरंभ से शून्य नहीं हो सकते हैं। उक्त तर्क को पलटने के लिए खंड पीठ का निम्नलिखित तर्क अंकित किए जाने योग्य है -

" यदि वे शुरू से ही अमान्य हो जाते हैं, यानी उनके किए जाने के तुरंत बाद, तो याचिका वापस लेने या खारिज होने पर, वे पुनर्जीवित नहीं होंगे। यह स्पष्ट है कि यदि याचिका

वापस ले ली जाती या खारिज कर दी जाती तो लेनदेन कभी भी अमान्य नहीं होता। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि लेन-देन/व्यवहार शुरू से ही अमान्य नहीं हैं, बल्कि समाप्त करने के आदेश के पारित होने या अस्थायी परिसमापक की नियुक्ति पर अमान्य हो जाते हैं। धारा 536(2) को धारा 441(2) के साथ पढ़ने पर जो अन्यथा वैध था उसे शून्य में परिवर्तित करने का कानूनी कल्पना द्वारा प्रावधान है। इस प्रकार अस्थायी परिसमापक को नियुक्त करने के या कंपनी समाप्त करने के आदेश के पारित होने पर शून्यता प्रभावी होगी। धारा 441(2) की कानूनी कल्पना से यह फिर समाप्त करने के लिए याचिका प्रस्तुत करने की संबंधित पूर्व तिथि से मान्य होता है।"

हम वर्तमान में कंपनी अधिनियम की धारा 536(2) के प्रभाव पर विचार करेंगे। पूरा प्रावधान नीचे अंकित है:

" परिसमापन शुरू होने के बाद स्थानांतरण आदि से बचना -

(1) स्वैच्छिक समापन के मामले में, शेयरों का कोई भी हस्तांतरण, परिसमापक को या उसकी मंजूरी के साथ किए हस्तांतरण के बजाए, और सदस्यों की स्थिति में कोई परिवर्तन, जो समापन की शुरुआत के बाद किया गया है, शून्य हो जाएगा।

(2) न्यायालय द्वारा या उसके पर्यवेक्षण के अधीन एक समापन के मामले में, कंपनी की संपत्ति का कोई भी निपटान (अनुयोज्य दावा सहित) और कंपनी में शेयरों का कोई भी हस्तांतरण या इसके सदस्यों की स्थिति में परिवर्तन, परिसमापन प्रारंभ होने के बाद किया गया हो तो शून्य हो जाएगा जब तक कि न्यायालय अन्यथा आदेश नहीं देता।"

प्रासंगिक रूप से कंपनी अधिनियम की धारा 441(2) बहुत प्रासंगिक है इसलिए नीचे अंकित है:

"441. न्यायालय द्वारा समाप्त किए जाने की शुरुआत - जहाँ, किसी कंपनी को बंद करने के लिए अदालत में याचिका प्रस्तुत करना से पहले, कंपनी द्वारा स्वैच्छिक रूप से समापन हेतु एक प्रस्ताव पारित किया गया है, कंपनी का समापन प्रस्ताव के पारित होने के समय से शुरू होना माना जाएगा, और जब तक कि अदालत धोखाधड़ी या गलती के सबूत पर अन्यथा निर्देश देना उचित नहीं समझती है कंपनी द्वारा स्वैच्छिक समापन में की गई सभी कार्यवाहियों का वैध रूप से लिया जाना माना जाएगा।

(2) किसी भी अन्य मामले में, न्यायालय द्वारा किसी कंपनी का समापन उसकी याचिका की प्रस्तुति के समय शुरू होना माना जाएगा।"

कंपनी अधिनियम के भाग VII (धारा 425 के अनुसार) में समापन के तीन तरीके निर्धारित किए गए हैं। पहला है, अदालत द्वारा समाप्त किया

जाना, अगला कंपनी द्वारा स्वैच्छिक रूप से समापन किया जाना और तीसरा न्यायालय की देखरेख में समापन किया जाना।

हमें धारा 536 की उपधारा (1) से खुद को परेशान करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह कंपनी को स्वेच्छा से बंद करने के मामले से संबंधित है, और अपीलों के वर्तमान समूह में से कोई भी कंपनी ऐसी आकस्मिकता में शामिल नहीं है। उपधारा (2) अन्य दो प्रकार के समापन से संबंधित है।

कंपनी अधिनियम की धारा 439 कंपनी को बंद करने के लिए अदालत में एक आवेदन का प्रारूप तैयार करती है। इसमें कंपनी अधिनियम के धारा 439 की उपधारा (1) में उल्लिखित किसी भी व्यक्ति द्वारा याचिका प्रस्तुत कि जा सकती है। ऐसे व्यक्तियों में लेनदार सहित संभावित लेनदार शामिल हैं।

एक बार बंद करने के लिए याचिका प्रस्तुत की जाती है तो यह आवश्यक नहीं है कि इसके बाद समापन होगा। यह स्थिति धारा 440(2) में स्पष्ट की गई है जिसमें कहा गया है कि "अदालत उप-धारा (1) के तहत उसे प्रस्तुत की गई याचिका पर समापन आदेश नहीं देगी, जब तक कि यह संतुष्ट नहीं हो जाता है कि स्वैच्छिक रूप से समापन या न्यायालय के अधीन समापन लेनदार या अंशदाता या दोनों के हितों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय की दृष्टि में जारी नहीं रखा जा सकता है।"

इसलिए अदालत की संतुष्टि तक पहुंचने के लिए एक न्यायिक अभ्यास की आवश्यकता है कि ऋणदाताओं या योगदानकर्ताओं के हित को ध्यान में रखते हुए समापन जारी रखा जाना चाहिए। कंपनी अधिनियम की धारा 443 इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है। उस धारा की उप-धारा (1) में कहा गया है कि समाप्त करने के लिए याचिका की सुनवाई करने पर न्यायालय या तो (1) याचिका को खारिज कर सकता है या (2) कोई अंतरिम आदेश दे सकता है जैसा वह उचित समझता है या (3) समाप्त करने का आदेश दे सकता है। उप-धारा (2) में कहा गया है कि "जहां याचिका इस आधार पर प्रस्तुत की जाती है कि यह उचित और न्यायसंगत है कि कंपनी का समाप्त होना चाहिए, यदि न्यायालय कि यह राय है कि याचिकाकर्ताओं के लिए कोई अन्य उपाय उपलब्ध है और वे उस अन्य उपाय को आगे बढ़ाने के बजाय कंपनी को समाप्त करने की मांग में अनुचित तरीके से काम कर रहे हैं, तो न्यायालय समाप्त करने का आदेश देने से इनकार कर सकता है।

इस संदर्भ में दो और प्रावधान प्रासंगिक हैं। धारा 450 में कहा गया है: "समापन याचिका की प्रस्तुति के बाद और समापन आदेश देने से पहले किसी भी समय, न्यायालय परिसमापक अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है जो अस्थायी रूप से परिसमापक होना।" अस्थायी परिसमापक की नियुक्ति से पहले अदालत को कंपनी को नोटिस देना होता है और अपना प्रतिनिधित्व करने का उचित अवसर देना होता है। धारा 449 में आदेश दिया गया है कि "किसी कंपनी के संबंध में बंद करने का आदेश दिए जाने

पर आधिकारिक परिसमापक, अपने पद के आधार पर, कंपनी का परिसमापक बन जाएगा।

केवल उपरोक्त पृष्ठभूमि में हम धारा 536(2) में विधायी निर्देश के प्रभाव पर विचार कर सकते हैं कि कंपनी की संपत्ति का कोई भी निपटान परिसमापन की शुरुआत के बाद (अर्थात् परिसमापन याचिका प्रस्तुत करने के बाद) अमान्य होगा। यहाँ दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहला यह है कि "शून्य" शब्द को स्वचालित रूप से यह इंगित करने की आवश्यकता नहीं है कि कोई भी स्वभाव प्रारंभ से ही शून्य होना चाहिए। "शून्य" शब्द का कानूनी निहितार्थ सभी परिस्थितियों में शून्यता का चरण होना आवश्यक नहीं है। ब्लैक लॉ डिक्शनरी "शून्य" शब्द का अर्थ अलग-अलग अर्थों में अलग-अलग बारीकियों के रूप में देती है। उनमें से एक निश्चित रूप से "शून्य, या कोई कानूनी बल या बाध्यकारी प्रभाव नहीं है"। और दूसरा "कानून में असमर्थ है, उस उद्देश्य का समर्थन करने के लिए जिसके लिए इसका इरादा था"। इसके बाद शून्य और शून्यकरणीय के बीच की बारीकियों का उल्लेख करते हुए लेक्सीकोग्राफर ने निम्नलिखित को इंगित किया:

"'शून्य' शब्द का कठोर भाव में अर्थ उससे है जिसका कोई बल और प्रभाव नहीं हो, जो कानूनी प्रभावकारिता के बिना हो, जिसे कानून द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, या

जिसका कोई कानूनी या बाध्यकारी बल नहीं हो, लेकिन अक्सर इस शब्द का उपयोग अधिक उदार अर्थ रखने 'शून्यकरणीय' के रूप में किया जाता है । 'शून्य' शब्द का उपयोग कानूनों में इस अर्थ में किया जाता है कि पूरी तरह से शून्य हो जिसका सुधार नहीं किया जा सकता, और शून्यकरणीय के तौर पर भी तथा कई मामलों में यह निर्धारित करने के लिए कि विधानमंडल कि मंशा किस अर्थ में है कानूनों की व्याख्या करने के नियमों का पालन करना चाहिए। एक कार्य या अनुबंध जो न तो अपने आप में गलत है और न ही सार्वजनिक नीति के विरुद्ध है, जिसे कानून द्वारा किसी निश्चित पक्ष या पक्षकारों के वर्ग का संरक्षण या लाभ के लिए अमान्य घोषित किया गया है केवल शून्यकरणीय होगा।"

कंपनी अधिनियम की धारा 536(2) में निर्धारित संदर्भ में "शून्य" शब्द का उपयोग करने में विधायी विचार को समझने के लिए ध्यान देने योग्य दूसरा पहलू यह है कि प्रावधान स्वयं दर्शाता है कि शून्य का प्रयोग पूर्व में ही नहीं होता क्योंकि अदालत अन्यथा आदेश देने में सक्षम हैं। शब्द "जब तक अदालत अन्यथा आदेश न दे" "शून्य" शब्द की कठोरता को कम करने और उस शब्द से जुड़े वैकल्पिक अर्थ को चुनने में सक्षम हैं।

चित्तूर जिला सहकारी मार्केटिंग सोसायटी लिमिटेड v. मेसर्स वेगेटोल्स लिमिटेड और अन्य, [1987] एसे.सी.सी 167, में इस अदालत की दो न्यायाधीशों की पीठ ने कंपनी बंद करने के लिए एक याचिका प्रस्तुत करने के बाद एक कंपनी द्वारा किए गए भुगतानों के सत्यापन के लिए एक याचिका पर विचार किया।

कुछ भुगतान समापन आदेश के पारित होने से पहले और कुछ उसके बाद भुगतान किए गए। इस न्यायालय ने इस प्रकार भुगतान को मान्य करने से इस आधार पर इनकार कर दिया कि "यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि वे भुगतान या तो कंपनी की संपत्ति को बचाने या उसकी रक्षा करने के लिए परिस्थितियों की मजबूरी में किए गए थे या वहाँ कोई व्यवसाय चलाने में सक्षम बनाने के लिए वाणिज्यिक मजबूरी थी"। निर्णय केवल यह इंगित करता है कि इस तरह के भुगतान को वैध बनाया जा सकता था यदि परिस्थितियों की मजबूरी दिखाने के लिए सबूत होता। वास्तव में, यह निर्णय इस व्याख्या का समर्थन करता है कि समापन की कार्यवाही शुरू होने के बाद जो भुगतान किए गए थे, वे शुरू से शून्य हो जाता है।

बॉम्बे उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ का एक प्रारंभिक निर्णय *तुलसीदास जसराज पारेख बनाम इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ वेस्टर्न इंडिया*, AIR (1931) Bombay 2 पर अधिकांश विद्वान वकीलों द्वारा भरोसा करने की

मांग की गई थी जिन्होंने अलग-अलग अपीलार्थी की ओर से तर्क दिया था। जिस प्रश्न पर न्यायालय ने विचार किया वह पुराने कंपनी अधिनियम, 1913 की धारा 227(2) से संबंधित था जो वर्तमान अधिनियम की धारा 536(2) के समान था। एक कंपनी द्वारा कुछ भुगतान बंद करने की कार्यवाही शुरू होने के बाद किए गए जिस पर सवाल उठाए गए और खंड पीठ ने उप-धारा के दायरे पर विचार किया और देखा कि यह सिद्धांत अंग्रेजी कंपनी अधिनियम से लिया गया था। इसलिए कुछ अंग्रेजी निर्णयों को मार्टन मुख्य न्यायाधीश द्वारा भी संदर्भित किया गया था, जिन्होंने डिवीजन बेंच के लिए निर्णय दिया था। विद्वान न्यायाधीशों ने इस प्रकार कहा:

"अब यहां धारा 227(2) के संबंध में न्यायालय को दो चरम विकल्पों के बीच का रास्ता ढूंढना होगा। धारा एक तरफ किसी भी बिक्री या भुगतान को शामिल करने के लिए पर्याप्त विस्तृत है जो एक कंपनी समापन याचिका की तारीख के बाद कर सकती है। उस आधार पर यदि कोई याचिका प्रस्तुत की जाती है तो उसे व्यावहारिक रूप से किसी भी व्यवसाय को बंद करना होगा, क्योंकि कंपनी की किसी भी संपत्ति का निपटान करना असुरक्षित होगा। उदाहरण के लिए, एक मिल कंपनी अपनी भट्टियों के उपयोग के लिए एक टन कोयला खरीदने में सक्षम नहीं हो

सकती है या, दूसरी ओर, हो सकता है कि वह अपनी किसी भी वस्तु को व्यवसाय के सामान्य अनुसरण में बेचने में सक्षम न हो। नतीजतन, न्यायालय ने बहुत उचित रूप से निर्धारित किया है कि, सामान्य रूप से, वर्तमान व्यवसाय के सामान्य अनुसरण में की गई और पूरी की गई किसी भी मौजूदा हस्तांतरण कार्रवाई को न्यायालय द्वारा धारा 227(2) के तहत मंजूरी दी जाएगी। दूसरी ओर यह कंपनी का मनमाने रूप से परिसंपत्तियों का निपटान नहीं होने देगा और इस प्रकार मौलिक सिद्धांत का कारण बनता है कि लेनदारों के बीच समानता का उल्लंघन नहीं किया जाए। ऐसा करना धारा 230 में एक और अधिमान्य श्रेणी जोड़ा जाना होगा जिसमें वो सभी ऋणों को जोड़ा जाएगा जिन्हें कंपनी पूरा या आंशिक रूप से भुगतान हेतु चुन सकती है।"

डिवीजन बेंच गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा *नवजीवन मिल्स लिमिटेड, In Re (1986) 59 Company Cases 201*, में द्वारा अपनाए गए तर्क को संदर्भित करना उपयोगी है जिस मामले में एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने के पक्ष में जब एक कंपनी द्वारा अदालत से कुछ प्रवृत्तियों की मंजूरी के लिए संपर्क किया गया था जो समापन के लिए याचिका प्रस्तुत करने के बाद किए गए थे। यह डिवीजन बेंच द्वारा

समापन आदेश पारित करने के समय और उसके बाद के समय के बीच एक स्पष्ट अंतर तैयार किया गया था। निम्नलिखित व्यक्त विचार उक्त मुद्दों पर चिंतन करने के लिए उपयोगी हैं:

"अदालत कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 536(2) के तहत समापन याचिका के लंबित रहने के दौरान प्रस्तावित लेनदेन को मान्य करने वाले निर्देश देने के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकती है लेकिन उन्हें परिसमापन आदेश से पहले करना होगा क्योंकि जब तक कि इन लेनदेन को समापन होने के परिणाम से बचाया नहीं जाता है तो, हो सकता है कि कंपनी खुद को चालू रखने को मुश्किल पाए और इसका व्यवसाय लकवाग्रस्त हो जाए। न्यायालय में शक्ति के निवेश का अंतर्निहित उद्देश्य कंपनी के लाभ और हित के लिए है ताकि यह सुनिश्चित करना कि एक कंपनी जिसे समापन याचिका का विषय बनाया गया है, फिर भी अपने व्यवसाय को पूरा करने के लिए आवश्यक धन प्राप्त कर सकती है और ताकि उसके व्यवसाय को लकवाग्रस्त होने से बचाया जा सके। यदि इस खंड का उद्देश्य और लक्ष्य यही है, तो शक्ति को कम करना और इसके संचालन को प्रतिबंधित करना शायद ही उचित और न्यायसंगत होगा।

क्योंकि अन्यथा करने पर इसका विपरीत- प्रभाव इस आशय से होगा कि कंपनी को एक चालू रखने का उद्देश्य उसके शेयरधारकों और लेनदारों के हितों को सुनिश्चित किया जा सके जो पराजित होंगे।"

इन रे ग्रेज इन कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (1980) 1 ALL E.R. 814 में अपील न्यायालय (सिविल डिवीजन) ने उस सिद्धांत पर विचार किया जिसके अन्तर्गत इंग्लिश कंपनी अधिनियम 1948 की धारा 227 जो लगभग भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 536(2) के समान है जिसमें परिसमाप्ति याचिका प्रस्तुत करने और बंद करने के आदेश के बीच के अंतराल के दौरान किसी कंपनी द्वारा की गई संपत्ति के निपटान को मान्य करने के लिए न्यायालय को विवेकाधिकार दिया गया है। व्यवहार जो हो सकते हैं निर्णय में उल्लेखित है। उक्त निर्णय का उल्लेख हमारे सामने पहले किया गया था इस बात पर जोर देने के लिए कि अदालतें भुगतान और लेनदारों के ब्याज को मान्य करने के मामले में बहुत चौकस होंगी, और साथ ही कंपनी को विचार में सबसे ऊपर रखा जाएगा। हालाँकि, उक्त निर्णय इस तर्क का समर्थन करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि अंतराल के दौरान व्यवहार अपरिवर्तनीय रूप से शून्य होगा।

यह निर्धारित करना मुश्किल है कि संपत्ति के सभी निपटान एक कंपनी को बंद करने के लिए एक याचिका की प्रस्तुति और बंद करने के

आदेश के पारित होने के बीच के अंतराल के दौरान अमान्य होगा। यदि ऐसा दृष्टिकोण लिया जाता है तो कंपनी का व्यवसाय लकवाग्रस्त होगा क्योंकि कंपनी को कई दिन-प्रतिदिन के लेनदेन से निपटना पड़ सकता है, कर्मचारियों और अन्य कर्मियों को वेतन का भुगतान करना पड़ सकता है और तत्काल आकस्मिकताओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी व्याख्या को टाला जाना चाहिए जो ऐसी विनाशकारी स्थिति का कारण बन सकती है। इसके अलावा, यदि ऐसा कोई दृष्टिकोण अपनाया जाता है, तो एक धोखाधड़ी वाली कंपनी ऐसे ईमानदार ग्राहकों को हराने के लिए कंपनी को बंद करने के लिए प्रस्तुत की जाने वाली याचिका का प्रबंधन करके चरणबद्ध तरीके से कंपनी के साथ व्यापार करने वाले किसी भी ईमानदार व्यक्ति को धोखा दे सकती है। डिवीजन बेंच द्वारा विवादित फैसले में इस नतीजे को सही ढंग से व्यक्त किया गया है।

यदि भुगतान शुरू से ही अमान्य नहीं है तो कंपनी यह विरोध नहीं कर सकती कि चेक के अनादर के संबंध में जब प्राप्तकर्ता द्वारा नोटिस जारी किया गया था तो चेक राशि का भुगतान करने से कानूनी रूप से मना किया गया था। इस बाधा को दरकिनार करने के लिए कुछ अपीलार्थियों द्वारा एक प्रयास किया गया था यह दिखाने के लिए कि चेक जारी करना ही संपत्ति का निपटारा होता है। हम इस तर्क से सहमत नहीं हैं जो मुख्य रूप से पराक्रम लिखित अधिनियम के अन्तर्गत चेक की परिभाषा से दर्शित होता है। "चेक" एक ऐसा विनिमय -पत्र है जो विनिर्दिष्ट बैंकर पर लिखा

गया है और जिसका माँग पर से अन्यथा देय होना अभिव्यक्त नहीं है एवं उसमें इलेक्ट्रानिक रूपक से निकाला हुआ छंटित चैक तथा इलेक्ट्रानिक रूपक सम्मिलित है ।

बिल ऑफ एक्सचेंज "विनिमय-पत्र" ऐसी लेखबद्ध लिखत है जिसमें एक निश्चित व्यक्ति को यह निदेश देने वाला उसके रचयिता द्वारा हस्ताक्षरित अशर्त आदेश, अन्तर्विष्ट हो कि वह एक निश्चित व्यक्ति को या उसके आदेशानुसार या उस लिखत के वाहक को ही धन की एक निश्चित राशि संदत्त करे। इसलिए, चेक बैंकर को उसके धारक को राशि का भुगतान करने का आदेश हो सकता है और संपत्ति का कोई निपटान जब तक कि बैंकर द्वारा इसके अनुसार भुगतान नहीं किया जाता है नहीं हो सकता है अधिक से अधिक, चेक की निकासी को संपत्ति का निपटान की दिशा में एक कदम माना जा सकता है, लेकिन यह संपत्ति के निपटान के लिए अपर्याप्त है।

इसके बाद यह तर्क दिया गया कि चूंकि पराक्रम लिखित अधिनियम की धारा 138 के अन्तर्गत अपराध गठन की एक शर्त यह है कि जारी किया गया चेक कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या अन्य दायित्व के निर्वहन के लिए जारी किया गया था और इस प्रकार का कोई भी चेक इसी परिस्थिती में नहीं बनाया जा सकता क्योंकि समापन कार्यवाहियों की

शुरुआत होने से लेनदार कानूनी रूप से ऋण को लागू करने से अक्षम हो जाएगा।

निसंदेह, धारा 138 में किसी भी व्यक्ति द्वारा ऋण या अन्य दायित्व का पूर्ण या आंशिक रूप से निर्वहन के लिए जारी किया जाता है। धारा 138 के स्पष्टीकरण में कहा गया है कि "इस धारा के प्रयोजनों के लिए" "ऋण या अन्य 'दायित्व'" का अर्थ है कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या दायित्व है। इसलिए तर्क का सबसे पहला अंग में बल है कि धारा 138 के तहत अपराध के लिए चेक कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या अन्य भुगतान के लिए तैयार किया जाना चाहिए था। लेकिन तर्क का दूसरा अंग कमजोर है क्योंकि ऋण केवल इसलिए कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं रहेगा क्योंकि किसी ने बंद करने के लिए याचिका दायर की है। इस संदर्भ में अधिनियम की धारा 139 का एक संदर्भ स्पष्ट है। वह इस प्रकार है:

139. धारक के पक्ष में उपधारणा - जब तक कि अन्यथा साबित न कर दिया जाये, यह उपधारणा की जायेगी कि बैंक के धारक ने वह बैंक धारा 138 में निर्दिष्ट किसी ऋण अथवा अन्य दायित्व के भागतः या पूर्णतः उन्मोचन के लिए प्राप्त किया है ।

इस प्रकार, जब किसी धारक को चेक प्राप्त होता है तो अदालत को यह मान लेना पड़ता है कि (1) यह धारा 138 में निर्दिष्ट प्रकृति का

चेक है; और (2) ऐसा कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या दायित्व के निर्वहन के लिए चेक प्राप्त किया गया था। यह एक कानूनी आदेश है कि अदालत को इस उपधारणा के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि धारक द्वारा कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या दायित्व के निर्वहन के लिए चेक प्राप्त किया गया था जब तक कि जारीकर्ता अन्यथा साबित नहीं कर देता है। विद्वान वकील ने तर्क दिया कि जारीकर्ता पर पड़ा सबूत का बोझ टल जाता है और उपधारणा का खण्डन हो जाता है जब यह दर्शित कर दिया जाए कि कंपनी को बंद करने की कार्यवाही में लाया जा चुका है अतः किसी भी ऋण को कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है।

कंपनी अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो किसी कंपनी से देय ऋण के प्रवर्तन को प्रतिबंधित करता हो। जब कोई कंपनी परिसमापन में जाती है, कंपनी से देय ऋण का प्रवर्तन केवल समापन में अंकित शर्तों के अधीन होता है। लेकिन इससे यह मानने के लिए कोई आधार नहीं है कि ऋण कानूनी रूप से अप्रवर्तनीय है। शायद कंपनी के पास पर्याप्त संपत्ति नहीं होने से ऋण की वसूली कठिन होगा। इससे यह नहीं माना जा सकता कि ऋण कानूनी रूप से अप्रवर्तनीय है। ऋण की प्रवर्तनीयता का परीक्षण प्राप्ति या पुनर्प्राप्ति के लिए प्रदान की गई पद्धति या प्रक्रिया की कसौटी पर नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए यह तर्क कि कंपनी से देय ऋणों और देनदारियों के संबंध में कंपनी अधिनियम में विशेष प्रावधान

शामिल किया गया है जो ऋण को अप्रवर्तनीय बना देगा, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

वैकल्पिक तरीका यह है कि: यह मानते हुए भी कि परिसमापन की कार्यवाही शुरू होने के बाद किसी कंपनी द्वारा बनाई गई संपत्ति अमान्य व शून्य है, यह अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध से बचने का आधार कैसे है? उक्त धारा ने एक विधिक अपराध बनाया है जो उसमें अंकित किए गए विभिन्न कारकों का संगम है, जो चेक के आहरण के साथ शुरू होता है और चेक के लेखीवाल द्वारा निर्धारित समय के भीतर उसके द्वारा चेक राशि का भुगतान करने में विफलता के साथ समाप्त होना दंडात्मक दायित्व में बदल जाता है।

धारा 138 के तहत अपराध का गठन करने के लिए अंतिम कारक धारा के परंतुक के खंड (ग) में दिया गया है जो इस प्रकार है: "लेखीवाल उस सूचना की प्राप्ति के पन्द्रह दिन के अंदर उस व्यक्ति को जो बैंक के अधीन राशि प्राप्त करने वाला हो अथवा जो सामान्य अनुक्रम में बैंक का धारक हो, उस राशि का संदाय करने में असफल नहीं रहता है।"

शब्द "इस तरह के चेक का लेखवाल भुगतान करने में विफल रहता है" स्पष्ट रूप से यह कहने से अलग हैं कि "लेखवाल भुगतान करने से इनकार करता है"। भुगतान नहीं करना किसी ऐसे कारण से हो सकता है जो लेखवाल के वश से बाहर हो। उदाहरण के तौर पर व्यक्ति जो इतना

गरीब या इतना बीमार हो गया है कि वह मांगी गई राशि का भुगतान करने के लिए धन नहीं जुटा सकता। क्या वह यह तर्क दे सकता है कि चूंकि भुगतान करने में विफलता ऐसी शर्तों के कारण थी, इसलिए वह बरी होने का हकदार है? उत्तर सकारात्मक नहीं हो सकता है, हालांकि उपरोक्त शर्तों को सजा के प्रश्न पर विचार करते समय सामने रखा जा सकता है।

इसलिए हम महसूस करते हैं कि विधायिका ने सोच-समझकर "विफल" शब्द का अन्य अभिव्यक्तियों के बजाय इस्तेमाल किया है क्योंकि विफलता विभिन्न प्रकार के कारण से हो सकती है। लेकिन अपराध पूरा हो जाएगा जब लेखवाल निर्धारित समय के भीतर भुगतान करने में "विफल" हो जाता है, इस तरह की विफलता का कारण जो भी हो। चेक के लेखवाल के पास चेक राशि का भुगतान करने में विफलता के अलग-अलग स्पष्टीकरण हो सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई भी स्पष्टीकरण उसे उक्त धारा में अंकित अपराध से बचाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। हालांकि इस तरह का स्पष्टीकरण उसे अपराध की कठोरता को कम करने के लिए पर्याप्त हो सकता है जो अधिरोपित किए जाने वाले दंड की मात्रा को कम करने में उपयोगी हो सकता है। लेकिन इस स्तर पर इस पर विचार करने का कोई आधार नहीं है।

उपरोक्त सभी कारणों से, हम बंबई उच्च न्यायालय के विवादित फैसले में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। लेकिन, अपीलों के इस समूह

में अपीलार्थियों में से एक अपीलकर्ता (अताश इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड) की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि खण्डपीठ द्वारा एक टिप्पणी की गई है जो कंपनी पर मुकदमें के साथ आगे बढ़ने पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। हमने देखा कि विवादित फैसले के पैराग्राफ 59 में की गई टिप्पणी उनके खिलाफ पूर्वाग्रह पैदा करने की शक्ति रखती है जो निम्नलिखित है:

"अताश इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड का आचरण तथ्यों को दमन करने और सही तथ्यों को इंगित किए बिना न्यायालयों से आदेश प्राप्त करना पदच्युत किया जाना चाहिए। हमारे विचार में कंपनी का यह आचरण उसे कोई भी न्यायसंगत राहत दिलाने से निषेध करता है।"

हम यह स्पष्ट करते हैं कि टिप्पणी उच्च न्यायालय में लंबित केवल रिट याचिका के लिए कि गई थी और उसे कंपनी के खिलाफ विचारण के शेष चरणों के दौरान नहीं गिना जाएगा। तदनुसार सभी याचिकाएं खारिज कर दी जाती हैं।

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

यह अनुवाद आटिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सुवास की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी प्रवीण शंकर (आर.जे.ऐसे.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्याहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणित होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।